The Sameeksha Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 4, Issue 1 – 2020
ISSN: 2581-401X

भारत में शिक्षा प्रणाली की विरासत और वर्तमान

Heritage and current Education system in India

डॉ. अजय कृष्ण तिवारी[1]

[1]*Sr.Lecturer CTE/ BTTC/ IASE-G.V.M & Former H.O.D, Department of Education, IASE Deemed to be University, Sardarshahar.*

Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

शुरुआत में (Introduction)

प्राचीन काल में, भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी जिसमें जो कोई भी अध्ययन करना चाहता था वह शिक्षक (गुरु) के घर जाता था और उसे पढ़ाने का अनुरोध करता था। यदि गुरु द्वारा एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वह गुरु के स्थान पर रहेगा और घर में सभी गतिविधियों में मदद करेगा। इसने न केवल शिक्षक और छात्र के बीच एक मजबूत संबंध बनाया, बल्कि छात्र को घर चलाने के बारे में सब कुछ सिखाया। गुरु ने वह सब कुछ सिखाया जो बच्चा सीखना चाहता था, संस्कृत से पवित्र शास्त्रों तक और गणित से लेकर तत्वमीमांसा तक। छात्र जब तक चाहे तब तक रहे या जब तक गुरु को यह महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वह उन्हें सिखाया जा सकता है। सभी सीखने को प्रकृति और जीवन से निकटता से जोड़ा गया था, और कुछ जानकारी को याद रखने तक ही सीमित नहीं था।

आधुनिक स्कूल प्रणाली को अंग्रेजी भाषा सहित भारत में लाया गया था, मूल रूप से 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बिंगटन मैकाले द्वारा। पाठ्यक्रम को "आधुनिक" विषयों जैसे विज्ञान और गणित तक सीमित कर दिया गया था, और तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को अनावश्यक माना गया था। शिक्षण कक्षाओं तक सीमित था और प्रकृति के साथ संबंध टूट गया था, शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध भी।

उत्तर प्रदेश (भारत का एक राज्य) बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन 1921 में राजपूताना, मध्य भारत और ग्वालियर पर अधिकार क्षेत्र के साथ भारत में स्थापित किया गया पहला बोर्ड था। 1929 में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा, राजपूताना के बोर्ड की स्थापना हुई। बाद में, कुछ राज्यों में बोर्ड स्थापित किए गए। लेकिन अंततः1952 में, बोर्ड के

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

संविधान में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कर दिया गया। दिल्ली और कुछ अन्य क्षेत्रों के सभी स्कूल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं।

यह बोर्ड का कार्य था कि वह इससे जुड़े सभी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा प्रणाली जैसी चीजों पर निर्णय ले। आज बोर्ड से संबद्ध हजारों स्कूल हैं, भारत के भीतर और अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक कई अन्य देशों में।6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा भारत गणराज्य की नई सरकार का एक सपना था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 45 में एक निर्देश नीति के रूप में शामिल किया गया है।

लेकिन यह उद्देश्य आधी सदी के बाद भी बहुत दूर बना हुआ है। हालाँकि हाल के दिनों में, सरकार ने इस चूक पर गंभीरता से ध्यान दिया है और प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया है।

आर्थिक विकास के दबाव और कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की तीव्र कमी ने निश्चित रूप से सरकार को ऐसा कदम उठाने के लिए एक भूमिका निभाई है। भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में स्कूली शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3þ है, जिसे बहुत कम माना जाता है।

“हाल के दिनों में, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खराब स्थिति के विकास के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की गईं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) घोषणाएँ हैं;

a) जीडीपी के लगभग 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि करना।
b) शिक्षा पर व्यय में वृद्धि और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सभी केंद्र सरकार के करों पर एक शिक्षा उपकर लगाया जाएगा।
c) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के कारण किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता है।
d) ६-१४ वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

e) अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि सर्वशिक्षा अभियान और मिड डे मील के माध्यम से शिक्षा को व्यापक बनाना। "भारत में शिक्षा।

स्कूल प्रणाली (School system)

भारत 28 राज्यों और 7 तथाकथित "केंद्र शासित प्रदेशों" में विभाजित है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर भारत सरकार द्वारा सीधे शासन किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार, स्कूली शिक्षा मूल रूप से एक राज्य का विषय था- इसलिए, राज्यों को नीतियां तय करने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार था। भारत सरकार (भारत सरकार) की भूमिका उच्च शिक्षा के मानकों पर समन्वय और निर्णय लेने तक सीमित थी। इसे 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के साथ बदल दिया गया था ताकि शिक्षा अब तथाकथित समवर्ती सूची में आए। अर्थात्, स्कूली शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों का राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया जाता है, हालांकि राज्य सरकारों को कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत अधिक स्वतंत्रता है। नीतियों की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर समय पर की जाती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE), 1935 में स्थापित, शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के विकास और निगरानी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

एक राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) कहा जाता है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है। प्रत्येक राज्य का अपना समकक्ष राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) कहलाता है। ये वे निकाय हैं जो अनिवार्य रूप से शैक्षिक रणनीतियों, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाओं और शिक्षा के राज्यों के विभागों के मूल्यांकन के तरीकों का प्रस्ताव करते हैं। SCERT आमतौर पर NCERT द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन राज्यों को शिक्षा प्रणाली को लागू करने में काफी स्वतंत्रता है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 और कार्रवाई का कार्यक्रम (पीओए) 1992 ने 21 वीं सदी से पहले 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की थी। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6þ

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसका आधा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर खर्च भी 1951-52 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में लगभग 3.6 प्रतिशत हो गया।

भारत में स्कूल प्रणाली के चार स्तर हैं: निम्न प्राथमिक (आयु 6 से 10), उच्च प्राथमिक (11 और 12), उच्च (13 से 15) और उच्चतर माध्यमिक (17 और 18)। निम्न प्राथमिक विद्यालय को पाँच "मानकों" में विभाजित किया जाता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय को दो में, हाई स्कूल को तीन में और उच्चतर माध्यमिक को दो में विभाजित किया जाता है। छात्रों को उच्च विद्यालय के अंत तक बड़े पैमाने पर (मातृभाषा में क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़कर) एक सामान्य पाठ्यक्रम सीखना होता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुछ मात्रा में विशेषज्ञता संभव है। देश भर के छात्रों को तीन भाषाओं (अर्थात्, अंग्रेजी, हिंदी और उनकी मातृभाषा) को उन क्षेत्रों को छोड़कर सीखना है, जहाँ हिंदी मातृभाषा है और कुछ धाराओं में जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

भारत में स्कूली शिक्षा में मुख्य रूप से तीन धाराएँ हैं। इनमें से दो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित हैं, जिनमें से एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अधीन है और मूल रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए था जो समय पर स्थानांतरित होते हैं और देश में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। देश के सभी मुख्य शहरी क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए कई केंद्रीय विद्यालय (केंद्रीय विद्यालय नाम) स्थापित किए गए हैं, और वे एक सामान्य कार्यक्रम का पालन करते हैं ताकि एक विशेष दिन में एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने वाला छात्र शायद ही देख सके जो सिखाया जा रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं। एक विषय (सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र शामिल हैं) को हमेशा हिंदी और अंग्रेजी में अन्य विषयों में इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय अन्य बच्चों को भी स्वीकार करते हैं यदि सीटें उपलब्ध हैं। वे सभी NCERT द्वारा लिखित और प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का अनुसरण करते हैं। इन सरकारी स्कूलों के अलावा, देश में कई निजी स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, हालांकि वे विभिन्न पाठ पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम का पालन कर सकते हैं। उन्हें निम्न वर्गों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसमें एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता है। सीबीएसई के

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

21 अन्य देशों में 141 संबद्ध स्कूल हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं।

दूसरी केंद्रीय योजना भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) है। ऐसा लगता है कि यह कैंब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था। इस विचार को 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में लूटा गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा विदेशी कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के प्रतिस्थापन पर विचार करना था। अक्टूबर 1956 में एंग्लो-इंडियन एजुकेशन के लिए इंटर-स्टेट बोर्ड की बैठक में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए एक भारतीय परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया, भारत में स्थानीय परीक्षाओं की सिंडिकेट परीक्षा और सिंडीकेट को सलाह देने के लिए की जरूरतों के लिए अपनी परीक्षा को अनुकूलित करने का सबसे अच्छा तरीका है

केरल का मामला

केरल राज्य, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट का एक छोटा राज्य है, जो पिछले कुछ दशकों से देश के बाकी हिस्सों से कई मायनों में अलग है। उदाहरण के लिए, सभी राज्यों के बीच उच्चतम साक्षरता दर है, और लगभग एक दशक पहले पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया था। पुरुष और महिला दोनों की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है जो विकसित दुनिया के करीब है। अन्य मापदंडों जैसे कि प्रजनन दर, शिशु और बाल मृत्यु दर में सबसे अच्छे हैं, यदि सर्वोत्तम नहीं हैं। पिछले दो दशकों में कुल प्रजनन दर 2.1 की प्रतिस्थापन दर से नीचे रही है। संभवतः आर्थिक और सामाजिक विकास के साइड-इफेक्ट के रूप में, आत्महत्या की दर और शराबखोरी भी बहुत अधिक है। सरकार की नीतियां भी देश के बाकी हिस्सों से बहुत अलग रही हैं शिक्षा और कल्याण में उच्च व्यय के साथ केरल में विकास मॉडल के लिए अग्रणी, अर्थशास्त्रियों के बीच "केरल मॉडल" के रूप में जाना जाता है।

केरल ने भी अपनी स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के तरीकों को आजमाने में हमेशा रुचि दिखाई है। एनसीईआरटी हर बार नए विचारों के साथ आया, यह केरल था जिसने इसे सबसे पहले आजमाया। राज्य ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के साथ उत्साह के साथ प्रयोग किया, हालांकि विभिन्न तिमाहियों से इसका विरोध किया गया, और यहां तक कि इसे

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

प्राथमिक कक्षाओं से परे भी लिया। राज्य देश का पहला था जो पारंपरिक व्यवहारवादी तरीके से शिक्षण से सामाजिक रचनावादी प्रतिमान की ओर बढ़ा। इसका उल्लेख वर्ष 2000 में NCERT के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किया गया था, और केरल ने अगले वर्ष इसे आज़माना शुरू कर दिया। कक्षा में लेनदेन और मूल्यांकन पद्धति बदल दी गई। पाठों को याद करने के माध्यम से केवल पूछे जाने वाले प्रत्यक्ष प्रश्नों के बजाय, अप्रत्यक्ष प्रश्नों और खुले अंत वाले प्रश्नों को शामिल किया गया था ताकि छात्र को उत्तर देने से पहले सोचने की आवश्यकता हो, और उत्तर कुछ हद तक व्यक्तिपरक हो सकते हैं। इसका मतलब यह था कि छात्रों को उनके द्वारा पढ़ी गई बातों को पचाना पड़ता था और सवालों के जवाब देने के लिए एक विशिष्ट स्थिति में अपने ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होना पड़ता था। उसी समय, नई पद्धति ने बहुत अधिक दबाव ले लिया और बच्चों ने तनावपूर्ण होने के बजाय परीक्षाओं को दिलचस्प और सुखद खोजना शुरू कर दिया। इसके साथ एक व्यापक और सतत मूल्यांकन (CCE) प्रणाली शुरू की गई, जिसने छात्र के समग्र व्यक्तित्व को ध्यान में रखा और अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए एकल अंतिम परीक्षा पर निर्भरता कम कर दी। वर्तमान में, CBSE ने भी CCE लागू किया है, लेकिन अधिक लचीले तरीके से।

हाईस्कूल स्तर पर अध्ययन के विषय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने वाला केरल देश का पहला राज्य भी था। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत करने वाली पाठ्यपुस्तक के साथ कक्षा 8 में शुरू किया गया था। लेकिन एक वर्ष के भीतर सरकार को निशुल्क सॉफ्टवेयर उत्साही लोगों के विरोध और एक स्कूल शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए एक अनुकूल रुख के द्वारा निः शुल्क सॉफ्टवेयर को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें अधिकांश सरकारी शिक्षक इसके सदस्य थे। आखिरकार, वर्ष 2007 से, स्कूलों में केवल GNU/ स्पदन पढ़ाया जाता था, और स्कूलों में सभी कंप्यूटरों में केवल GNU/ स्पदन स्थापित थे। उस समय, शायद आज भी, यह स्कूलों में जीएनयू/ लिनक्स की सबसे बड़ी स्थापना थी, और अन्य देशों में भी सुर्खियों में बनी हुई थी। हर साल, 2007 से, लगभग 500,000 बच्चे निःशुल्क सॉफ्टवेयर और जीएनयू/ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोगों के पीछे की अवधारणाओं को सीखने वाले स्कूलों से बाहर निकलते हैं। राज्य अब आईटी सक्षम शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। आखिरकार, आईटी को एक

अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बजाय, सभी विषयों को आईटी की मदद से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे एक तरफ, आईटी कौशल सीखें और दूसरी तरफ, शैक्षिक अनुप्रयोगों (जैसे कि नीचे उल्लिखित) और इंटरनेट में संसाधनों का उपयोग करें विकिपीडिया, चित्र, एनिमेशन और वीडियो जैसी साइटों से पाठ्य सामग्री जैसे कि उनके विषयों का अध्ययन करने और अभ्यास करने के लिए। शिक्षकों और छात्रों ने पहले से ही डॉ। जियो, जियोनी और केटेकलैब जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग ज्यामिति और इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्ययन के लिए शुरू कर दिया है। Sunclock Kalzium और Ghemical जैसे एप्लिकेशन भी शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं।

केरल द्वारा की गई पहल अब अन्य राज्यों और यहां तक कि भारत सरकार की नीतियों को भी प्रभावित कर रही है। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य अब अपने स्कूलों में मुफ्त सॉफ्टवेयर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, और कुछ अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र विकल्प की जांच कर रहे हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति रचनावाद, आईटी सक्षम शिक्षा, मुफ्त सॉफ्टवेयर और शैक्षिक संसाधनों को साझा करने के बारे में बोलती है। एक बार कुछ बड़े राज्य सफलतापूर्वक फ्री सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, तो यह आशा की जाती है कि पूरा देश अपेक्षाकृत कम समय में सूट का पालन करेगा। जब ऐसा होता है, तो भारत में सामान्य रूप से जीएनयू/ लिनक्स और फ्री सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार हो सकता है।

संदर्भ

1. दत्ता इंद्रजीत, दत्ता नीती (2012) मिश्रित शिक्षण- स्मार्ट कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एक शैक्षणिक दृष्टिकोण। Edutracks 11: पी। 10.
2. हसन डी, राव ए.वी., अप्पा। शिक्षक शिक्षा में नवाचार। Edutracks (11): पी। 5.
3. कर्पगम एस।, अनंतशयनम आर। (2012) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल। Edutracks (11): पी। 1 1.
4. पद्मनाभन जयंती, राव मंजुला पी। (2011) विज्ञान में निर्माणवादी दृष्टिकोण और समस्या-समाधान की क्षमता। जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च; 28 (1): पीपी। 56-70.
5. राही पुनीत (2012)। शिक्षण-अधिगम में नवाचार। Edutracks (11): पी। 1 1.

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

6. राव रवि रंगा, राव दिगुमर्ती भास्कर (2014)। शिक्षक प्रशिक्षण के तरीके। डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2014.
7. शिक्षक शिक्षा में अभिनव व्यवहार, http%@@www-mu-ac-in@MAþ20 Teacherþ20 Education @ Chapter & 8Aþ 20 &þ 208B-pdfA.

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.